जहां राहुल गांधी के खाना खाने का इंतजाम, उसी टैंट में धरने पर बैठे किरोड़ी मीणा

किरोड़ी के धरना स्थल, अलवर-दौसा बॉर्डर पर सुरेर गांव में 19 दिसम्बर को पहुँचेंगे राहुल गांधी

अलवर/राजगढ़, 17 दिसम्बर (निसं)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौसा जिले के समापन व अलवर जिले के प्रवेश स्थल पर शनिवार को राज्यसभा सांसद व भाजपा नेता डॉ. किरोड़ी लाल मीणा बड़ी संख्या में लोगों के साथ पहुंच गए।

दौसा-अलवर बॉर्डर पर सुरेर गांव में जहां 19 दिसम्बर को राहुल गांधी के भोजन करने का इंतजाम किया गया था। उसी टैंट में डॉ. किरोड़ी बड़ी संख्या में युवाओं के साथ धरने पर बैठ गए। किरोड़ी अलग-अलग मुद्दों को लेकर राहुल गांधी को ज्ञापन देंगे।

डॉ. किरोड़ी शनिवार दोपहर अचानक सुरेर पहुंचे। उनके आने के कुछ देर बाद ही बड़ी संख्या में युवा वहां आ गए। देर शाम तक लोगों का आने का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार ने कोविड हेल्थ वर्कर्स से काम लिया, बाद में हटा दिया। उनके लिए सरकार कुछ करे। किसानों की जमीन अवाप्त कर ली, मुआवजा नहीं मिला। शराब कारोबारियों को संकट में डाल दिया, प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, कई अन्य मुद्दों को लेकर राहुल गांधी को ज्ञापन देकर अवगत कराएंगे। हो सकता है उनके संज्ञान में मामला आने के बाद सरकार बेरोजगारों के हित में कोई निर्णय लें। डॉ. किरोड़ी ने बड़ी संख्या में युवाओं के साथ धरने पर बैठने के बाद कहा कि वे उनको ज्ञापन देकर ही जाएंगे। चाहे राहुल गांधी दो दिन में आएं, तब तक यहां बैठे रहेंगे। उन्होंने प्रदेश भर के युवाओं को आव्हान भी किया कि वे भी

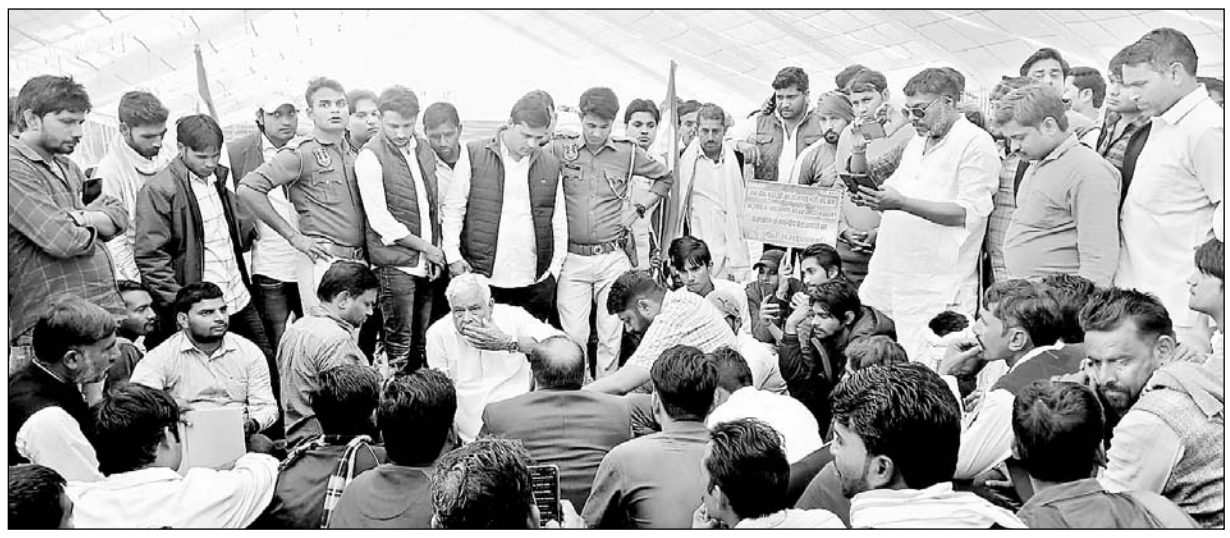

आगामी 19 दिसम्बर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिस जगह पर पड़ाव डालने वाली है, भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा उस जगह पर पहले ही पहुँच गये हैं। दरअसल, दौसा -अलवर बॉर्डर पर राहुल गांधी की यात्रा के दौरान भोजन का इंतजाम किया गया है। शनिवार को किरोड़ी लाल मीणा उसी टैंट में पहुँच गये और अपने समर्थकों की अच्छी -खासी भीड़ के साथ डेरा डालकर धरने पर बैठ गये।

- **शनिवार दोपहर अचानक किरोड़ी लाल मीणा सुरेर गांव पहुँचे, उनके साथ कई युवा भी आ गए और देर शाम तक लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा।**
- **किरोड़ी ने कहा कि, वे कोविड हैल्थ वर्कर, महिलाओं पर अत्याचार व किसानों की जमीन अवाप्ति जैसे कई मुद्दों पर राहुल को ज्ञापन देंगे।**

पहुंचें। हालांकि डॉ. किरोड़ी के आने के बाद प्रशासन बहुत अधिक अलर्ट हो गया है। इससे पहले, करोना के समय शराब कम बेचने पर लगी पेनल्टी समाप्त करने एवं कोविड स्वास्थ्य सहायकों को नियमित करने सहित अपनी मांगों को लेकर पीड़ितों ने सिकंदरा-अलवर मार्ग पर थाना राजाजी के पास जाम लगाया। इसके कारण वाहन चालकों सहित आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शराब ठेकेदार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पंकज धनखड़ ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम ओमप्रकाश मीणा को ज्ञापन दिया। इस जाम के कारण प्रशासन व पुलिस को समझाइश करनी पडी मगर आंदोलनकारी टस से मस नहीं हुए। करीब 2 घंटे पश्चात पुलिस प्रशासन ने माइक से कानून को अपने हाथ में नहीं लेने की चेतावनी देते रास्ता अवरुद्ध नहीं करने की अपील की। बाद में पुलिस प्रशासन ने आंदोलनकारियों को सड़क मार्ग से खदेड़ दिया। इससे पूर्व डॉ. किरोडी लाल मीणा ने टहला जा रहे राज्य सरकार के मंत्री बी.डी. कल्ला, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह एवं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सहित अन्य प्रतिनिधियों से समस्याओं के बारे में वार्ता की। इस अवसर पर भाजपा के विजय समर्थ लाल मीणा, सुनीता मीणा एवं शिवलाल मीणा सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

सरकार के 4 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सिक्योरिटी लागू कीजिए। केंद्र 200 रुपए की बुजुर्ग पेंशन देता है, 200 रुपए में क्या होता है? पूरे देश में नीति बने और सबको कम से कम 2000 से 3000 रुपए पेंशन मिले। इसमें आधा पैसा केंद्र सरकार और आधा राज्य दे।गहलोत ने कहा कि कर्मचारियों के लिए हमने ओपीएस लागू की, इसका विरोध भी हो रहा है। नीति आयोग ने विरोध किया, वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने विरोध किया है। दुनिया के कई अर्थशास्त्री इसका विरोध कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ओपीएस के खिलाफ है। गहलोत ने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री दिल्ली में जाकर सबके सामने गिड़गिड़ाए है कि हमें ओल्ड पेंशन लागू करने दो, नहीं तो चुनाव हार जाएंगे। उनकी एक बात नहीं सुनी गई और हिमाचल के नतीजों के एक दिन बाद एनके सिंह का स्टेटमेंट आ गया इसके खिलाफ। पीएम तो इसके शुरू से खिलाफ हैं।

मनरेगा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने मनरेगा को स्मारक कहा था। वो स्मारक ही मुश्किल वक्त में काम आया और आज भी काम आ रहा है। हमने मनरेगा से आगे बढ़कर शहरी नरेगा शुरू की है, राजस्थान पहला राज्य है, जहां शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में 25 एमपी जीताकर भेजे हैं। क्या वे ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा सकते?

महेन्द्र शांडिल्य हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित

बलराम वशिष्ठ महासचिव चुने गए

जयपुर, 17 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद पर महेन्द्र शांडिल्य विजयी हुए हैं। उन्हें 1621 मत मिले और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रहलाद शर्मा को 542 मतों से हराया।

वहीं महासचिव के पद पर बलराम वशिष्ठ विजयी रहे। उन्होंने संजय खेदड को 108 मतों से पराजित किया। इसी तरह उपाध्यक्ष के दो पदों पर नरेन्द्र कुमार और श्रवण सैनी विजयी हुए। जबकि संयुक्त सचिव के पद पर देवांग चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष पद पर हितेश मिश्रा, सामाजिक सचिव के पद पर शिल्पा शर्मा, पुस्तकालय सचिव के पद पर प्रमिला शर्मा और संयुक्त पुस्तकालय सचिव के पद पर नरेन्द्र शर्मा विजयी हुए।

इसी तरह कार्यकारिणी के आठ पदों के लिए मनीष सिंह तोमर, अभिषेक शर्मा, अंजनी कुमार शर्मा, सुनील कुमार शर्मा, कमलेश शर्मा, जगदीश नागर, सतीश कुमार बलवदा व समीर शर्मा को निर्वाचित किया गया। सुबह 11 बजे से शुरु होने वाली मतगणना तकनीकी कारणों के चलते करीब सवा बजे से शुरु हुई। वहीं पदाधिकारियों के मतों की गणना के दौरान कार्यकारिणी के पद के उम्मीदवार को मतगणना स्थल से बाहर निकालने के चलते वकीलों में तकरार हो गई। इस दौरान कुछ लोगों ने मतगणना हॉल की दो खिडकियों पर लगे कांच फोड दिए। इस पर पुलिस के आलाधिकारियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया।

- **शांडिल्य ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संजय खेदड़ को 108 मतों से हराया।**
- **मतगणना के दौरान एक-दो बार टकराव के हालात भी पैदा हो गए थे।**

पंजाबी नुस्खा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कितनी शराब की जरूरत होगी, ताकि यह शराब, गैर कानूनी शराब के प्रचलन वाले क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जा सके।''

पंजाब सरकार ने कहा कि उसने इस अदालत के वे निर्देश क्रियान्वित कर दिये हैं, जो राज्य में अवैध शराब के उत्पादन को रोकने के लिये दिये गये थे।

अदालत ने 5 दिसम्बर को भगवंत मान सरकार की खिंचाई करते हुये कहा था कि वह राज्य में अवैध शराब के अत्यधिक उत्पादन एवं बिक्री के खिलाब कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

अदालत ने यह भी कहा था कि सरकार इस मामले में केवल केस दर्ज कर रही हैं, लेकिन उसके बाद की कार्यवाही नहीं कर रही।

गुरुवार को, पंजाब सरकार ने उसके द्वारा जारी किये गये उस सर्कुलर का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया है कि अगर शराब बनाने वाली कोई ''भट्टी'' किसी क्षेत्र में पाई जाती है तो उसके लिये स्थानीय पुलिस अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा, अवैध शराब निर्माण की सूचना देने वाले व्यक्ति को 50,000 रू. से लेकर 1 लाख रू. तक का इनाम दिया जायेगा। इनाम की राशि की मात्रा जब्त हुई अवैध शराब की मात्रा पर निर्भर होगी।

इसके अलावा, एक सजगता-अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि लोगों को अवैध शराब पीने के दुष्परिणामों की जानकारी दी जा सके।

अल्पसंख्यकों को दी जा रही मौलाना आज़ाद नैशनल स्कॉलरशिप बंद की सरकार ने

यह छात्रवृत्ति एम. फिल व पी.एच.डी. की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को दी जाती है

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। केन्द्र सरकार के निर्णय ने एक विवाद को जन्म दे दिया है जिसके अन्तर्गत, एम.फिल. तथा पीएच.डी. कर रहे अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को दी जाने वाली मौलाना आज़ाद नैशनल फैलोशिप (एम.ए.एन.एफ.) तथा कक्षा 1 से 8 तक के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को मिलने वाली प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है।

एम.ए.एन.एफ. को रोकने के पीछे केन्द्र का तर्क यह है कि उच्च शिक्षा के लिये इस स्कीम के अलावा भी अन्य कई फैलोशिप स्कीम चल रही हैं। जहाँ तक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियों का संबंध है, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि 2009 के राइट टू एजुकेशन एक्ट ने सरकारों के लिये यह अनिवार्य कर दिया है कि वे कक्षा 8 तक के सभी बच्चों के लिये नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगी।

लेकिन विद्यार्थी इन तर्कों को स्वीकार करते प्रतीत नहीं हो रहे तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस निर्णय के बाद विरोध-प्रदर्शन शुरु हो सकते है।

इस बीच, विभिन्न राजनैतिक दलों के सांसदों ने इस निर्णय को वापस लिये जाने की माँग की है। मजेदार बात यह है कि महाराष्ट्र की बीड़ सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे भाजपा सांसद प्रीतम मुन्डे भी इस निर्णय की वापसी की माँग से जुड़ गये हैं।

एम.ए.एन.एफ. स्कीम, जस्टिस सच्चर कमेटी की 2005 की रिपोर्ट, जिसमें भारत की सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्थितियों का आकलन शामिल था, की सिफारिशों के फलस्वरुप वर्ष 2009 में शुरु की गई थी। किन्तु, अन्य अल्पसंख्यक समुदाय, जिनमें ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी तथा सिख-शामिल हैं, भी एक पंचवर्षीय फैलोशिप प्रोग्राम के तहत वित्तीय अनुदान के पात्र थे।

स्वयं सेवी संगठन, जैसे पुणे का पहचान फाउन्डेशन, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियों को रोक देने के सरकार के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं। इस संगठन के प्रवक्ता ने कहा, ''छात्रवृत्तियाँ सबसे पहले उन विद्यार्थियों की मदद के लिये शुरु की गई थीं, जो आर.टी. एक्ट का लाभ लेने की स्थिति में नहीं हैं। इस स्कीम को रोक देने का यह निर्णय समाज के एक वर्ग को शिक्षा से वंचित करने के समान है।''

जे.एन.यू. के प्रो. प्रवीण झा ने कहा कि शिक्षा के लिये भारत का बजट-आवंटन हर तरह से बहुत ही कम हैं। फैलोशिप तथा स्कॉलरशिप रोक देने के निर्णय से वे वर्ग निश्चित रूप से प्रभावित होंगे, जिन्हें इनसे कुछ न कुछ मिल रहा था।''

सरकार डेटा के अनुसार, 2014-15 से 2024-22 तक एम.ए.एन.एफ. फैलोशिप के लिये 6,722 विद्यार्थी चयनित किये गये थे।

- **यह छात्रवृत्ति प्री. मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे मुस्लिम विद्यार्थियों को भी दी जाती थी।**
- **अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति इरानी ने इस बारे में कहा कि, ये विद्यार्थी, जो हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिये इस छात्रवृत्ति का उपयोग कर रहे थे, उन्हें कई और सरकारी योजनाओं के तहत स्कॉलरशिप मिल रही है और मिल सकती है।**
- **स्मृति इरानी का, प्री-मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के बारे में भी यह भी कहना था कि, उन्हें शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) छात्रवृत्ति उपलब्ध है।**
- **पर, अल्पसंख्यक वर्ग इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है तथा कई विश्वविद्यालय, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, सरकार के इस आदेश के खिलाफ धरने प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं।**

'तीन नेताओं की अनुशासनहीनता पर 23 दिसम्बर को कार्यवाही होगी'

राजस्थान में कांग्रेस के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, खड़गे जी के पास रिपोर्ट है और उसी के आधार पर कार्यवाही होगी

जयपुर, 17 दिसम्बर (का.प्र.)। राजस्थान में 25 सितंबर को हुई समानांतर विधायक दल की बैठक और उसके बाद मिले तीन नेताओं के नोटिस को लेकर 23 दिसंबर को फैसला होने वाला है। राजस्थान में चल रही इसी राजनीतिक उठापटक को लेकर राजस्थान के प्रभारी बने सुखजिंदर सिंह रंधावा का कहना है कि वो तो नए आए हैं। पर खड़गे जी के पास अनुशासन समिति की जो रिपोर्ट गई है, उस पर 23 दिसंबर को बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इसमें विधायकों के इस्तीफे के साथ ही तीन नेताओं को मिले कारण बताओ नोटिस का मसला भी शामिल होगा। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को लेकर रंधावा ने कहा कि राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच कोई झगड़ा नहीं है। अगर झगड़ा होता तो दोनों नेता राहुल गांधी के दाएं-बाएं चलकर भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने की बजाय गुटबाजी करते नजर आते। इसी के साथ रंधावा ने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और नेताओं पर अपनी बात आलाकमान तक पहुंचाने में कोई रोक नहीं है, लिहाजा नेता भी अपनी बात खुलकर कहते हैं।

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने प्रेस कॉन्फ्रैंस को संबोधित किया।

- **रंधावा ने राजस्थान में गहलोत-पायलट प्रतिद्वंदिता को सिरे से खारिज कर दिया और कहा, यह सिर्फ मीडिया के दिमाग में है।**
- **विधायकों के इस्तीफा प्रकरण पर रंधावा ने यह कह कर टिप्पणी करने से मना कर दिया कि, उन्होंने अभी इस्तीफे नहीं देखे हैं।**

विधायक दल की समानांतर बैठक बुलाए जाने के आरोपी माने जा रहे तीन नेताओं पर कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि 23 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ होने वाली बैठक इन सभी बिन्दुओं पर बातें होंगी।

पायलट के सियासी स्टेटमेंट्स को लेकर उन्होंने कहा कि शुक्रवार को राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी पार्टी में डैमोक्रेसी है ओर कोई भी अपनी बात बोल सकता है। हर नेता को उसके विचार रखने का अधिकार है। भाजपा में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां मुंह खोलने वालों को पार्टी से चलता कर दिया जाता है। लेकिन हमारी पार्टी आज तक नेताओं की बात सुनकर उसका सम्मान करती आई है। पार्टी शीर्ष नेतृत्व हमेशा से ही नेताओं की बातों व विचारों को तरजीह देते आई है और उसे इंप्लीमेंट भी करती है। हालांकि, जो गलत है उस पर चर्चा होती है और फिर एक्शन होता है।

प्रभारी रंधावा ने आगे कहा कि गहलोत और पायलट के बीच सियासी खींचतान केवल मीडिया में चल रही है। असल हकीकत में ऐसा कुछ है ही नहीं। उन्हें कोई ग्रुपिज्म दिखाई नहीं दे रहा है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो पार्टी में विधायकों की राय को अधिक महत्व दिया जाता है। विधायकों के इस्तीफा प्रकरण पर उन्होंने कहा कि वो अतीत की बात नहीं करते हैं, बल्कि भविष्य पर ध्यान देते हैं और वर्तमान की बात करना पसंद करते हैं। विधायकों के इस्तीफे की तकलीफ मीडिया को अधिक है। आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक भी फिलहाल इस्तीफे की कॉपी नहीं देखी हैं और उसे देखने के बाद ही इस पर कोई टिप्पणी करेंगे। बावजूद इसके इस पर तो निर्णय स्पीकर को ही लेना है। ऐसे में उन्हें लगता है कि इस पूरे मसले पर स्पीकर ही बेहतर बता सकते हैं।

रंधावा ने राजस्थान और पंजाब में राजनीतिक परिस्थितियों में फर्क बताते हुए कहा कि पंजाब में आखिरी तीन महीने में संकट आया था। ऐसा राजस्थान में नहीं होगा। हमारे पास एक साल है। रंधावा ने कहा कि सबसे पहले उनका टास्क जिला, ब्लॉक और बूथ कमेटी के गठन का है। जिसे वो 10 से 15 दिन में पूरा करने की तैयारी में है। कांग्रेस में हर कम्युनिटी, हर वर्कर, किसने कितना काम किया है, उससे ज्यादा उसे रिवार्ड मिलेगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता कांग्रेस की बैकबोन हैं। चुनाव एम.एल.ए. नहीं, बल्कि कार्यकर्ता लड़ता है। अगर उसमें जोश है तो फिर जीत सुनिश्चित होती है।

13 साल पहले रिश्वत ली, अब सजा मिली

जयपुर, 17 दिसंबर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने बिजली का घरेलू कनैक्शन कराने के बदले 13 साल पहले 1100 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में रंगे हाथों पकड़े गए जे.वी.वी.एन.एल. के रीडर जगदीश प्रसाद मीणा को एक साल की सजा सुनाई है।

- **ए.सी.बी. अदालत ने जयपुर विद्युत वितरण निगम के रीडर जगदीश मीणा को 13 साल पहले 1100 रू. रिश्वत लेने के मामले में एक साल की सजा सुनाई।**

इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि, 15 सितंबर 2009 को परिवादी रामसहाय मीणा ने एसीबी में रिपोर्ट दी थी। जिसमें कहा गया कि, उसने गोनेर रोड के अपने मकान में बिजली का कनेक्शन लेने के लिए अपनी पत्नी के नाम जेवीवीएनएल में आवेदन किया था।

'अशोक गहलोत स्कूल ऑफ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बताया कि जन घोषणापत्र में किये गये 70 फीसदी से अधिक वादे तथा 85 फीसदी से अधिक बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारा है। कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण संभव हुआ है, जबकि राज्य सरकार के पास बजट में की गई घोषणाओं को लागू करने के लिये वित्तीय प्रबंधन, आवंटन के लिये कोई कार्ययोजना नहीं है। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2018 के विधानसभा चुनाव में व कांग्रेस के जनघोषणा पत्र में किसानों, युवाओं, महिलाओं, उद्यिमयों,व्यवसाइयों, बेरोजगारों से किये गये वादों का क्या हुआ? शहरों में नरेगा की तर्ज पर शहरी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की लॉन्चिंग वित्त वर्ष के 8 माह बाद में की, समन्वय समिति व कलेक्टरों को जो जिम्मेदारी दी,वो कागजों में ही है। करोनाकाल में पढ़ाई में हुये नुकसान की भरपाई के लिये स्कूली बच्चों को तीन माह की अवधि के ब्रिज कोर्स की बजट 2022-23 में घोषणा की, मुख्यमंत्री ने जुलाई 2022 में ब्रिज कोर्स की लॉन्चिंग की, लेकिन वर्तमान में किसी प्रकार से कोर्स स्कूलों में संचालित नहीं किया गया। पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री का कहना है कि, निरोगी राजस्थान के संकल्प के लिये मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, निशुल्क जांच योजना व मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने से राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ लागू करने वाला अग्रणी राज्य बन गया है, जबकि हकीकत में पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल, सेटेलाइट अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में ना दवाई, ना जांचों की सुविधा, ऑपरेशन के लिये पर्याप्त मात्रा में सर्जिकल उपरकरण इत्यादि की उचित व्यवस्था नहीं है, ना डॉक्टर्स और ना पेरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था नहीं है। मरीजों के परिजनों को पर्ची पर लिखी हुई दवाइयां अस्पताल के बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं,जांचें भी बाहर से करवानी पड़ रही है। जिससे महंगी दवाइयां और महंगी जांचें होने से मरीज के परिजनों पर आर्थिक भार पड़ रहा है। चिरंजीवी योजना में निजी अस्पतालों को समय पर इस योजना के क्लेम का भुगतान नहीं होने से अस्पताल कतरा रहे हैं, जिससे आमजन को परेशानी हो रही है। क्लेम के भुगतान में देरी होने व भ्रष्टाचार के कारण अस्पताल इलाज करने से दूरी बना रहे हैं। सम्पूर्ण किसान कर्जमाफी का राहुल गांधी ने 2018 में वादा किया था, कांग्रेस शासन में प्रदेश में 18817 किसानों की जमीनें कुर्क हो गई, 200 से अधिक किसानों ने सुसाइड कर लिया, सबसे अधिक किसानों की जमीनें अलवर में 04 हजार से अधिक किसानों की हुई हैं, जहां से 19 दिसंबर को राहुल गांधी यात्रा के जरिये जायेंगे, जिनके लिये कालीन बिछाने के लिये हरे पेड़ों तक को काट दिया गया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के संरक्षण में पेपर लीक का महाघोटाला हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी से जुड़े राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग भी इसमें शामिल हैं, जिससे प्रदेश की जनता वाकिफ है, सीबीआई जांच होगी तो बड़े चेहरों से नकाब उतर जायेगा। उन्होंने कहा कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा कि, 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे, जबकि गर्मियों में घंटों तक बिजली कटौती हुई और कोयला का संकट राज्य सरकार ने स्वयं पैदा किया, कम से कम 12 बार फ्यूल चार्ज बढ़ाया गया। बिजली पर कृत्रिम कमी करके उसका पावर परचेज के नाम पर महंगी बिजली खरीदकर चांदी कूटने का कार्य इस कांग्रेस सरकार ने किया है। कम्पनियों ने 16 से 18 रुपये प्रति यूनिट बिजली कंपनियों ने परचेज की। प्रदेश में बिजली उपलब्धता के हालात ऐसे हैं कि मिस-मैनेजमेंट के कारण जनता को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है और किसान को कड़ाके की सर्दी में रात के समय सिंचाई के लिये बिजली मिलने से काफी संख्या में किसानों की मौत हो गई। कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष के शासन में प्रदेश में 8 लाख 61 हजार से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, 7 हजार से अधिक हत्यायें, एक लाख 55 हजार से अधिक महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले, 25 हजार से अधिक दुष्कर्म के केस, देशभर में दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान पहले नंबर पर है, बच्चियों के तस्करी के मामले में नंबर वन, अवैध खनन में नंबर वन, महिला अपराध में दूसरे नंबर है।

धर्मांतरण

कोलकाता, 17 दिसंबर (वार्ता)। ईसाइयों के एक मंच बंगिया ईसाई परिशेबा (बीसीपी) ने शनिवार को कहा कि वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपेगा और उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह करेगा कि धर्म परिवर्तन कर अन्य धर्मों को ग्रहण करने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को धर्मांतरण से पहले के मिले हुए अधिकार उन्हें धर्मांतरण के बाद भी अधिकार मिलते रहें।

- **क्रिश्चियन फोरम ने मांग की है कि 'धर्मांतरण के बाद ईसाई बनने वाले लोगों को आरक्षण व अन्य अधिकार मिलते रहें'।**

बीसीपी के प्रदेश कार्यकारी सचिव हेरोड मुल्लिक ने यहां मीडियाकर्मियों से कहा, रूढ़िवादी समूह 1960 से मांग कर रहे हैं कि धर्मांतरण करने वाले एसटी समूह के लोगों के लोगों के लाभों को रद्द किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से वे झूठे प्रचार और घृणा अभियान चला रहे हैं। वे कथित तौर पर ईसाई समुदाय और चर्चों पर जघन्य हमले भी कर रहे हैं। राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को सौंपे जाने वाले ज्ञापन में हम उनसे कट्टरपंथी ताकतों के मंसूबों को विफल करने की अपील करेंगे।

'मन की बात में चीन की बात करें, प्र.मंत्री'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता एवं पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 25 दिसम्बर को प्रसारित होने वाले अपने ''मन की बात'' कार्यक्रम में उनके द्वारा पूछे गए सात प्रश्नों पर बात करनी चाहिए। रमेश ने कहा कि ''यह उनका राजनीतिक कर्त्तव्य एवं नैतिक जिम्मेदारी है क्योंकि देश इस बारे में जानना चाहता है।''

जयराम ने निम्न सात प्रश्न सामने रखे हैं:

1. 20 जून 2020 को अपने यह क्यों कहा कि भारतीय क्षेत्र के पूर्वी लद्दाख में चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की है?
2. आपने चीन को यह अनुमति क्यों दी कि वह पूर्वी लद्दाख के उन कई हजार किलोमीटर क्षेत्र में हमारी सेनाओं को आगे बढ़ने से रोके, जहां पर मई 2020 से पूर्व तक हमारे सैनिक नियमित पैट्रोलिंग कर रहे थे।
3. माउण्टेन स्ट्राइक कोर के गठन को लेकर 17 जुलाई 2013 को कैबिनेट में मंजूर योजना को आपने क्यों त्याग दिया?
4. आपने चीन की कम्पनियों को पी.एम. केयर्स फण्ड में अंशदान देने की अनुमति क्यों दी हुई है?
5. आपने पिछले दो वर्षों में चीन से रिकॉर्ड स्तर पर आयातों की अनुमति क्यों दी है?
6. आप इस पर क्यों जोर दे रहे हैं कि सीमा की स्थिति और चीन से मिल रही चुनौतियों पर संसद में बहाल नहीं होनी चाहिए।
7. आपने चीन के नेतृत्व से 18 बार मुलाकात की है, जो अभूतपूर्व है और आपने हाल ही बाली में शी ज़िनपिंग से हाथ मिलाया था। चीन ने उसके तुरंत बाद ही तवांग में घुसपैठ कर दी गई और वह सीमाई स्थिति को एकतरफा तरीके बदलना जारी रखे हुए है। आप देश को विश्वास में क्यों नहीं ले रहे हैं?

प्रधानमंत्री मोदी ने 3 अक्टूबर 2014 को ऑल इंडिया रेडियो (ए.आई.आर.) और दूरदर्शन पर जब पहली बार राष्ट्र के नाम संबोधन किया था।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908